GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 257
ANSWERED ON 19.03.2021

ASSET MONETIZATION OF RAILWAYS

257. SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government is planning for monetization of asset of Indian Railways;

(b) if so, the details thereof along with the reaction of Government thereto; and

(c) the investment expected from private and public sectors?

ANSWER

MINISTER OF RAILWAYS, COMMERCE & INDUSTRY AND CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(SHRI PIYUSH GOYAL)

(a) to (c): A Statement is laid on the Table of the House.

*****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (c) OF STARRED QUESTION NO. 257 BY SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR ANSWERED IN RAJYA SABHA ON 19.03.2021 REGARDING ASSET MONETIZATION OF RAILWAYS.

(a) and (b): Yes, Sir. Ministry of Railways has planned to monetize assets including Eastern and Western Dedicated Freight Corridors after commissioning, induction of 150 modern rakes through Public Private Partnership (PPP), station redevelopment through PPP, Railway land parcels, Multi functional complexes (MFC), Railway colonies, Hill Railways and stadiums. Ministry of Railways is committed towards enhancing the pace of infrastructure development, which is so vital for the national economy as a whole. In the strategy of investment led economic growth, Indian Railways would always be a key economic driver. Asset monetization would help in generating more resources towards infrastructure creation.

(c): Passenger train operations taken up through Public Private Partnership (PPP) is targeted to bring a total investment of about ₹ 30,000 crore. Asset Monetization involves various transaction processes, and the investment expected depends on the outcome of bidding process open to public and private sectors. Therefore, the actual investment expected from private and public sectors cannot be ascertained as of now.

***

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

19.03.2021 के

तारांकित प्रश्न सं. 257 का उत्तर

रेल परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण

***257 श्री जी.सी. चन्द्रशेखरः**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारतीय रेल की परिसंपत्ति का मुद्रीकरण करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) निजी और सरकारी क्षेत्र से कितना-कितना निवेश होने की उम्मीद है?

उत्तर

रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

रेल परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के संबंध में दिनांक 19.03.2021 को राज्य सभा में श्री जी.सी. चन्द्रशेखर द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.257 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित **विवरण।**

(क) और (ख): जी हां। रेल मंत्रालय ने परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण (मोनेटाइज) की योजना बनाई है, जिसमें कमीशनिंग के बाद पूर्वी और पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) के जरिए 150 आधुनिक रेक शामिल करना, पीपीपी के जरिए स्टेशन पुनर्विकास, रेलवे लैंड पार्सल, बहु कार्यात्मक परिसर (एमएफसी), रेलवे कालोनियां, हिल रेलवे और स्टेडियम शामिल हैं। रेल मंत्रालय अवसंरचना विकास की गति बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो समग्र रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निवेश आधारित आर्थिक विकास की कार्यनीति में भारतीय रेल सदैव महत्वपूर्ण आर्थिक वाहक होगी। परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण (मोनेटाइजेशन) से अवसंरचना सृजन के तहत अधिक संसाधन सृजित करने में सहायता मिलेगी।

(ग): सार्वजनिक निजी साझेदारी के जरिए शुरू किए गए यात्री गाड़ी परिचालन से लगभग 30,000 करोड़ रु. के कुल निवेश का लक्ष्य रखा गया है। परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण में विभिन्न संव्यवहार प्रक्रियाएं शामिल हैं और संभावित निवेश सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के लिए खोली गई बोली प्रक्रिया के परिणाम पर निर्भर करता है। इसलिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से संभावित वास्तविक निवेश का फिलहाल पता नहीं लगाया जा सकता है।

*****

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Sir, divisional headquarters of the Railways in Gulbarga was announced eight years back in the Budget of 2014 by the then Minister, Khargeji. Kalyana Karnataka region has given five MPs to BJP Government. Despite that, why is there such negligence towards this project?

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, at the outset, the question is unrelated to the original question. Secondly, whether a State gives five MPs or fifty, Prime Minister, Narendra Modiji, on day one, announced that this Government is a Government for the entire country, the entire 135 crores Indians, and we do not differentiate between one State and the other. We work for every State in the country. As regards new divisions, studies were conducted. The announcement was made without a detailed feasibility study of carving out a new division. Thereafter, since the announcement was made on the eve of elections and without any adequate study, it was necessary to have a study conducted. A very detailed study was conducted and it was found to be unfeasible.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Second supplementary.

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Sir, already eight years have passed by. When are you going to start this?

SHRI PIYUSH GOYAL: I have just said that it is found to be unfeasible.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : महोदय, यह मेरा पूर्व क्षेत्र था। गुलबर्गा में डिवीज़न करने की बात, इस पर स्टडी करने के बाद ही announce की गई थी। उस वक्त Railway Board में श्री मित्तल साहब Chairman थे, जो Kubdi, Dharwad के General Manager भी थे। उन्होंने ही यह निर्णय किया था कि तीन स्टेट्स को मिलाकर, गुलबर्गा में एक डिवीज़न बनाया जा सकता है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब इसको तीन ज़ोन्स में बांटा गया था, तब Gulbarga में Headquarter बनाकर इसको एक जगह पर लाया गया था। जिस समय उन्होंने ऐसा करना तय किया, उसी वक्त यह announcement हुई और इसके लिए लैंड भी दिया गया, साथ ही वहां fencing भी हुई। अगर यह feasible नहीं था, तो उसी वक्त आप वह लैंड वापस कर सकते थे।

श्री पीयूष गोयल : उपसभापति महोदय, वास्तव में देश भर में कई ऐसे प्रपोज़ल्स अलग-अलग जगहों से नई डिविज़न्स बनाने के लिए आते है, ज़ोनल जनरल मैनेजर्स उन्हें रेलवे बोर्ड को भेजते हैं और फिर रेलवे बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह उसके ऊपर पूरा होलिस्टिक व्यू ले, ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव से व्यू ले, आखिर ज़ोनल जनरल मैनेजर एक ज़ोन के जेएम थे। गुलबर्गा डिविज़न,

जैसे माननीय नेता विरोधी दल खुद कह रहे हैं कि वह तीन अलग-अलग डिविज़न्स को रिपोर्ट करता था, तो पूरी चीज़ का चारों दिशाओं में क्या इम्पैक्ट होगा, यह सब स्टडी करने का दायित्व रेलवे बोर्ड का रहता है। जहां तक मुझे ध्यान है, उन्होंने कमिटी ऑफ एक्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर्स या एसएजी ऑफिसर्स की कमिटी बैठाकर इसे स्टडी किया। इसके साथ-साथ देश में और कई प्रपोज़ल्स थे और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का भेदभाव करना उचित नहीं रहेगा क्योंकि मान लो आज मैं मंत्री हूं तो मैं मुम्बई के डिविज़न्स में कुछ भी हेर-फेर करूं, क्योंकि मैं आज मंत्री हूं और मैं मुम्बई का निवासी हूं! मैं समझता हूं कि इस पर प्रेक्टिकल व्यू प्वाइंट लेना पड़ता है, ऑपरेशनल फीज़िबिलिटी देखनी पड़ती है, खर्चे कितने बढ़ रहे हैं, उनका लाभ क्या होगा , यह सब देखना पड़ता है। फिर भी मैं माननीय नेता विरोधी दल के पास स्वयं जाऊंगा, रिपोर्ट और डिटेल्स लेकर जाऊंगा और उनके साथ चर्चा करूंगा।

श्री उपसभापति: माननीय जफर इस्लाम जी।

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Sir, I would like to ask the second supplementary.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Have you not put the second supplementary?

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: No, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Sir, the Ministry issued a notification on freezing of jobs after it had announced to hand over 151 trains to private operators. Is it not snatching the employment opportunity of common people? On the one side, the Government talks about 'Atmanirbhar Bharat', and on the other side, we see, Germany and France based companies are top five private players. Sir, what does the Government want to say about this?

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I would request the hon. Member to put on his headphones for translation because I want to say something in Hindi, and then I will respond in English to him. सर, हिन्दी में एक कहावत है -'शेखचिल्ली की जॉब्स '। इसमे शेखचिल्ली की कहानी है कि एक आदमी सपने में सोचता है कि जॉब्स आने वाली हैं और उन जॉब्स का सपना सोचते हुए यह बात करना...**(व्यवधान)**.. जॉब लॉसेज़ होंगे, क्योंकि निजी निवेश आयेगा...**(व्यवधान)**.. यह उस प्रकार की कहानी है। ...**(व्यवधान)**..

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Sir, ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(**Interruptions**)... Nothing is going on record. ...(**Interruptions**)... मंत्री जी, प्लीज़ आप बोलिये। ..(**व्यवधान**)..

श्री पीयूष गोयल: सर, देश में आज आवश्यता है कि अति आधुनिक ट्रेनें आएं, आवश्यकता है कि जितना अधिक पूरे नेटवर्क का युटिलाइज़ेशन हो, उतनी अधिक देश की जनता को सेवा मिले। यह पूरा सदन जानता है कि प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे को ऐतिहासिक बजट एलोकेशन मिला है। पिछली सरकार 40-45 हज़ार करोड़ रुपये हर वर्ष एलोकेट करती थी, इस वर्ष 2 लाख 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश मिला है। उसके बावजूद अगर देश की आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखें तो देश की रेल सुविधाओं में और ज्यादा बढ़त करने के लिए, नई ट्रेनें लाने के लिए आज 50 लाख करोड़ रुपये भी कम पड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में यह बड़ा लॉजिकल है कि जो व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, मैंने कल या परसों भी उदाहरण दिया था कि अगर रोड बनती है, तो रोड के ऊपर स्वाभाविक है कि सबकी गाड़ियां चलती हैं। ऐसे ही पाइपलाइन बनती है, अगर 'गेल' पाइपलाइन बनाये और सिर्फ 'गेल' की गैस उसमें जाए और बाकी किसी को अपने उद्योग के लिए गैस भेजनी है तो वह अलग पाइपलाइन बनाये, यह तो एक प्रकार से देश के नेचुरल रिसोर्सेज़ का दुरुपयोग होगा, देश का पैसा वेस्ट होगा। इसी प्रकार से एक बार रेलवे की पटरी लग गई तो उस पर अधिक से अधिक अच्छी ट्रेनें चलें, उसके लिए अगर निजी लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आएं, ट्रेनें चलायें, अच्छी ट्रेनें, मॉडर्न ट्रेन्स, उनकी अच्छी स्पीड हो, उनमें सेफ्टी हो तो मेरे ख्याल से उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है ...(व्यवधान).. और लोग तो उसमें काम करेंगे ही...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति: प्लीज़, बैठकर बात न करें।

श्री पीयूष गोयल: उसमें जॉब लॉसेज़ का सवाल कहां है ? आखिर वह ट्रेन भी कोई लोको पायलट चलायेगा। हमने तो कहा है कि लोको पायलट हम देंगे। उसमें गार्ड भी होगा, उसमें भी सर्विसेज़ होंगी, चाहे वह सिक्युरिटी हो, केटरिंग हो, तो जॉब लॉसेज़ का सवाल ही नहीं है।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्यगण मैं माननीय सैयद जफर इस्लाम जी को बुलाऊं, उसके पहले मैं माननीय जी.सी. चन्द्रशेखर को बताना चाहता हूं कि पहले ही सवाल में आपने दो सवाल पूछ लिये। आजकल देखता हूं कि सभी माननीय सदस्य एक ही साथ चार सवाल पूछते हैं, उससे दूसरों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि दो सप्लिमेन्टरी प्रश्न पूछने हैं तो एक-एक अलग पूछिये और जिन्हें एक सवाल पूछना है, वे एक ही सवाल पूछें। माननीय सैयद जफर इस्लाम, आप बोलिये।

SHRI SYED ZAFAR ISLAM: Sir, hon. Railway Minister is doing an exceptional job as Railway Minister. But, through you, I would like to request him to just give a sense of level of participation of private players in laying the railway track especially between

Kanpur and Allahabad, given the congestion is leading to not only delays, but also, loss of revenues because trains are not running up to their total speed.

SHRI PIYUSH GOYAL: Hon. Deputy Chairman, Sir, in the Railways rather than just haphazard announcements which used to happen earlier, we are focussing on a very committed plan which has been converted into the National Rail Plan, 2030. I fully appreciate the hon. Member's concerns because this route from Delhi towards the Eastern India passing through Allahabad, Kanpur and Lucknow, this entire route is by and large always chock-a-block, there is very little additional capacity to introduce new trains. Sir, we have two plans in mind for that. One, we have identified seven such routes where we will create dedicated passenger corridors which will be high-speed corridors where modern trains will run. Those are under DPR, the studies are going on right now; detailed project reports are being prepared. Once they are ready, we will see the feasibility. We are talking to State Governments, what support they will give whether they will give land or right of way along the existing highways or proposed highways. I am delighted to share with the Members, through you Sir, that the Government of Uttar Pradesh is giving us extremely good cooperation. The Chief Minister himself has talked to me about identifying this route going from Delhi all the way up to Varanasi passing through all these important historic and religious towns. We are looking at creating a dedicated passenger corridor for semi high-speed trains on this, mostly elevated along the highways. Once the DPR is ready, we will consider how to move further on that route.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, privatization is somewhat controversial. But the word 'asset monetization' is somewhat neutral and therefore this Government is using the word 'asset monetization'. Two days ago, the hon. Minister said, "no plan to privatize Indian Railways". But, there is plan to asset monetize Indian Railways. He defines 'asset monetization' as giving value to an asset and selling it off, which is privatization.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please ask your question.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, what did he say? He said, we will monetize and sell Eastern and Western Dedicated Freight Corridor, privatized; Railway colony, asset monetized, sold, privatized.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Jairam Rameshji, please ask your question.

SHRI JAIRAM RAMESH: Hill Railways, privatized; Stadiums, privatized.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please ask your question.

SHRI JAIRAM RAMESH: This asset monetization is a '*Mukhota*', that is actually privatization.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, thank you.

SHRI JAIRAM RAMESH: He has admitted it and he is contradicting his own statement which he gave in this House two days ago.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I feel very sad that such a learned hon. Member is not able to understand the simple meaning between privatization and monetization....(Interruptions)...

श्री उपसभापति: प्लीज़। बैठ कर कमेंट न करें।

SHRI PIYUSH GOYAL: When you privatize, you are selling off your assets permanently and it no more remains a part of the Government ownership. What I mentioned in my reply on the discussion on the Railways as well as in the reply given today, is very categorical. It says, we plan to monetize these assets after commissioning, induction of 150 modern rakes through Public Private Partnership (PPP). All of these are in terms of how these will help us to generate resources, will help us to support further investments, further growth of the Railways. I mentioned that day very clearly that the infrastructure of the Indian Railways will never be privatized, it will remain with the Indian Railways, it will be a part of Indian Railways. The dedicated freight corridor is a separate entity. It is a private limited or a limited company, a separate corporate entity, which is implementing these projects. Railways is supporting them, but, is not the owner of the track that DFC is laying, it is owned by the dedicated freight corridor company themselves. As regards the private trains or other assets, if we raise funds by leasing them out, by giving them out to private sector to use in the interim period, I think, we are doing service to the nation because that money will then help us to create better facilities which is a common demand of the entire country today.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No.258, Dr. Santanu Sen. He is not present. Any supplementary? Shri Jyotiraditya M. Scindia.